भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1302

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 08 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947(शक) को दिया जाना है)

गरीब नागरिकों की कम आय

1302. **श्री मुरारी लाल मीना :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के सबसे गरीब नागरिकों की औसत दैनिक आय अत्यंत कम है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान औसत दैनिक आय का राज्य वार ब्यौरा- क्या है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान अमीर वर्ग की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जबकि गरीब वर्ग की आय तुलनात्मक रूप से स्थिर रही है या घट रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि वर्तमान आर्थिक नीतियां अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ;और

(ङ) क्या सरकार आगामी वर्षों में निम्न आय वर्ग की आय बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारत में, आय का वर्ग वितरण संबंधी डेटा केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है। तथापि, उपभोग व्यय के संदर्भ में आय के वितरण को दर्शाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के अनुमानों का उपयोग परोक्ष रूप में किया जा सकता है।

नवीनतम एचसीईएस 2023-24 के अनुसार, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2022-23 में ₹3773 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹4122 हो गया, और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2022-23 में ₹6459 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹6996 हो गया है। इसके अलावा, असमानता के प्रमुख माप, गिनी गुणांक, में पर्याप्त सुधार हुआ है, जो वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 0.266 से घटकर 0.237 और शहरी क्षेत्रों में 0.314 से घटकर 0.284 हो गया है। वर्ष 2022-23 के स्तर से वर्ष 2023-24 में औसत एमपीसीई में वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारत की आबादी के निचले 5 से 10 प्रतिशत के लिए अधिकतम रही है।

इसके अलावा, वर्ष 2005-06 से नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत में बहुआयामी गरीबी संबंधी डिस्कशन पेपर के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान 24.8 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं।

हाल ही में वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए जारी एचसीईएस आंकड़ों के आधार पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य-वार औसत एमपीसीई ***अनुलग्नक I*** में दी गई है।

(ग), (घ) और (ङ): जी, नहीं। सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों का विकास करना है। समावेशी विकास पर सरकार का विशेष बल गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करने तथा देश की आबादी के संवेदनशील वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "सबका साथ, सबका विकास" की प्रतिबद्धता से परिलक्षित होता है।

इन उद्देश्यों के साथ, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य संवेदनशील समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रमों; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के तहत निधि अंतरण, पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों का का भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी कॉपरेटिव्स के लिए ब्याज संबंधी सहायता; फार्म गेट अवसंरचना आदि के लिए कृषि अवसंरचना निधि जैसे कई लक्षित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार ने आधारभूत सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के माध्यम से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन-धन योजना आदि सहित विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है।

सरकार का बहु-आयामी दृष्टिकोण है जो आर्थिक असमानता को दूर करता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है और निष्पक्ष आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार को प्राथमिकता देता है। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट यह दर्शाती है कि शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में, श्रम बाजार में कोविड-पूर्व के स्तर की तुलना में सुधार हुआ है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो गई है।

रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके अलावा, पर्याप्त पूंजीगत व्यय, लॉजिस्टिक सुविधाओं में निरंतर सुधार, शहरी विकास, एमएसएमई को बढ़ावा देने, कृषि और विनिर्माण जैसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे नागरिकों की रोजगार और क्रय शक्ति में सुधार हुआ है।

सरकार कौशल विकास केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्किल, री-स्किल और अप-स्किल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी लागू कर रही है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस भविष्य के लिए तैयार करना है। इसके अलावा, पीएम विश्वकर्मा योजना अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करने के लिए सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। भारत में प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था है, जिसमें उच्च ब्रैकेट में शामिल एक व्यक्ति निम्न आय ब्रैकेट में शामिल व्यक्ति की तुलना में उच्च दरों पर आयकर का भुगतान करता है। इसके अलावा, आयकर पर अधिभार एक निश्चित स्तर से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। इस प्रकार, आय अर्जकों के उच्च ब्रैकेटों के कराधान की तुलना में मजबूत कराधान प्रणाली पहले से ही मौजूद है।

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपायों का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया है कि नई कर व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। बजट में करदाताओं को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत आयकर के स्लैब और दरों में बदलाव का भी प्रस्ताव किया गया है। नई संरचना से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आने और उनके पास अधिक पैसा उपलब्ध रहने की संभावना है। मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के अन्य उपायों में बढ़ी हुई पेंशन योजनाएं, किफायती आवास के लिए सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाएं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए औसत एमपीसीई (₹ में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	5,327	7,182
अरुणाचल प्रदेश	5,995	9,832
असम	3,793	6,794
बिहार	3,670	5,080
छत्तीसगढ़	2,739	4,927
दिल्ली	7,400	8,534
गोवा	8,048	9,726
गुजरात	4,116	7,175
हरियाणा	5,377	8,428
हिमाचल प्रदेश	5,825	9,223
झारखंड	2,946	5,393
कर्नाटक	4,903	8,076
केरल	6,611	7,783
मध्य प्रदेश	3,441	5,538
महाराष्ट्र	4,145	7,363
मणिपुर	4,531	5,945
मेघालय	3,852	7,839
मिजोरम	5,963	8,709
नागालैंड	5,155	8,022
ओडिशा	3,357	5,825
पंजाब	5,817	7,359
राजस्थान	4,510	6,574
सिक्किम	9,377	13,927
तमिलनाडु	5,701	8,165
तेलंगाना	5,435	8,978
त्रिपुरा	6,259	8,034
उत्तर प्रदेश	3,481	5,395
उत्तराखंड	5,003	7,486
पश्चिम बंगाल	3,620	5,775
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,771	10,453
चंडीगढ़	8,857	13,425
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,311	6,837
जम्मू एवं कश्मीर	4,774	6,327
लद्दाख	5,010	7,533
लक्षद्वीप	6,350	6,377
पुडुचेरी	7,598	8,637
अखिल भारत	**4,122**	**6,996**

वर्ष 2022-23 में प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए औसत एमपीसीई (₹ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
आंध्र प्रदेश	4,870	6,782
अरुणाचल प्रदेश	5,276	8,636
असम	3,432	6,136
बिहार	3,384	4,768
छत्तीसगढ़	2,466	4,483
दिल्ली	6,576	8,217
गोवा	7,367	8,734
गुजरात	3,798	6,621
हरियाणा	4,859	7,911
हिमाचल प्रदेश	5,561	8,075
झारखंड	2,763	4,931
कर्नाटक	4,397	7,666
केरल	5,924	7,078
मध्य प्रदेश	3,113	4,987
महाराष्ट्र	4,010	6,657
मणिपुर	4,360	4,880
मेघालय	3,514	6,433
मिजोरम	5,224	7,655
नागालैंड	4,393	7,098
ओडिशा	2,950	5,187
पंजाब	5,315	6,544
राजस्थान	4,263	5,913
सिक्किम	7,731	12,105
तमिलनाडु	5,310	7,630
तेलंगाना	4,802	8,158
त्रिपुरा	5,206	7,405
उत्तराखंड	4,641	7,004
उत्तर प्रदेश	3,191	5,040
पश्चिम बंगाल	3,239	5,267
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7,332	10,268
चंडीगढ़	7,467	12,575
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4,184	6,298
जम्मू एवं कश्मीर	4,296	6,179
लद्दाख	4,035	6,215
लक्षद्वीप	5,895	5,475
पुडुचेरी	6,590	7,706
अखिल भारत	**3,773**	**6,459**